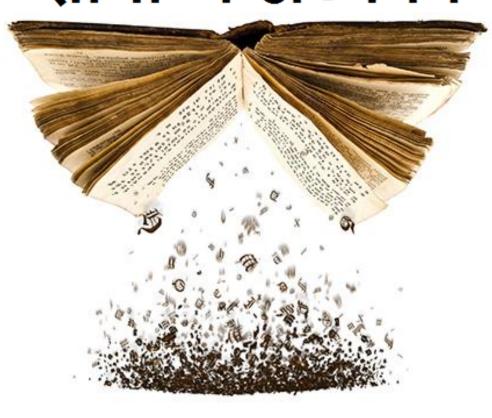


VISION IAS

www.visionias.in

P174

भारतीय समाज सामान्य अध्ययन







VISIONIAS

www.visionias.in

Classroom Study Material

भारतीय समाज

नगरीकरण

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. परिचय (Introduction)	3
2. नगरीकरण और संबंधित परिघटनाएँ	3
2.1. नगरीय संकुल (Urban Agglomeration)	4
2.2 अति-नगरीकरण (Over-Urbanization)	4
2.3 उप-नगरीकरण (Sub-Urbanization)	4
2.4 प्रति-नगरीकरण (Counter-Urbanization)	4
2.5 जनगणना नगर (Census Town)	5
3. नगरीकरण की प्रक्रिया (Process of Urbanization)	5
4. भारत में नगरीकरण (Urbanization in India)	
5. नगरीकरण के सामाजिक प्रभाव	8
5.1 परिवार और नातेदारी (Family and Kinship)	
5.2 नगरीकरण और जाति	8
5.3 नगरीकरण और महिलाओं की स्थिति	9
6. नगरीकरण की समस्याएँ	9
6.1 आवास एवं भूमि के बढ़े हुए मूल्य	
6.2. आवास तथा मलिन बस्तियां (Housing and Slums)	11
6.3. अत्यधिक भीड़-भाड़ (Overcrowding)	11
6.4. जल आपूर्ति, जल निकासी एवं स्वच्छता	11
6.5. परिवहन एवं यातायात व्यवस्था	11
6.6. प्रदूषण (Pollution) 7. नगरीकरण और अभिशासन	12
7. नगरीकरण और अभिशासन	12
	14
9. आगे की राह (Way forward)	15
9.1. समावेशी शहर (Inclusive Cities)	
9.2. वित्तीयन (Financing)	15
9.3. नियोजन (Planning)	15
9.4. स्थानीय क्षमता निर्माण	16
10. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न	16
11. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए प्रश्न	28
usPramesh eLib	
www.pluspramesh.in	

1. परिचय (Introduction)

नगरीकरण, वास्तव में शहर बनने, शहरों की ओर प्रवास करने, कृषि के स्थान पर शहरों में प्रचलित अन्य सामान्य व्यवसाय जैसे कि व्यापार, विनिर्माण, उद्योग और प्रबंधन को अपनाने तथा इन्हीं के अनुरूप व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। यह अंतर्संबंधों की सम्पूर्ण व्यवस्था में विस्तार की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जनसंख्या स्वयं को वास स्थान में बनाए रखती है।

कस्बों और नगरों के आकार में वृद्धि के परिणामस्वरूप नगरीय जनसंख्या में बढ़ोत्तरी होना, नगरीकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। प्राचीन काल में रोम और बगदाद जैसे कई प्रमुख नगर रहे हैं, किन्तु जब से औद्योगीकरण तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, नगरों का असाधारण रूप से विकास हुआ है। अत: कहा जा सकता है कि वर्तमान में नगरीकरण हमारे समकालीन जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बन गया है।

वैश्विक नगरीय जनसंख्या

वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स, 2014 के अनुसार विश्व की नगरीय जनसंख्या का आधा भाग कुछ ही देशों में निवास करता है। विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या (758 मिलियन) चीन में वास करती है तथा उसके पश्चात् भारत (410 मिलियन) का स्थान आता है। इन दो देशों में विश्व की नगरीय जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत निवास करता है। इन दोनों देशों के साथ यदि संयुक्त राज्य अमेरिका (263 मिलियन), ब्राज़ील (173 मिलियन), इंडोनेशिया (134 मिलियन), जापान (118 मिलियन) तथा रूस (105 मिलियन) की नगरीय जनसंख्या को मिला दें तो ये सम्मिलित रूप से विश्व की नगरीय जनसंख्या के आधे से अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत में नगरीकरण मुख्यत; स्वतंत्रता पश्चात् की परिघटना है। इसका मुख्य कारण भारत द्वारा अर्थव्यवस्था की मिश्रित प्रणाली का अपनाया जाना है जिसने निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया। भारत में नगरीकरण बहुत तीव्र गति से जारी है। 1901 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या 11.4% थी। यह 2001 की जनगणना में बढ़कर 28.53% तथा 2011 की जनगणना में 30% के पार पहुँच गई। वर्तमान में भारत की नगरीय जनसंख्या 31.16% है।

2. नगरीकरण और संबंधित परिघटतूर्ण्एँ

(Urbanization and Associated phenomenon)

एक नगरीय बस्ती की निर्माण प्रक्रिया की कोई सर्वनिष्ठ वैश्विक परिभाषा नहीं है। विभिन्न देशों में उनके राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा प्रयुक्त नगर की परिभाषा भिन्न-भिन्न होती है तथा कुछ मामलों में कई देशों में इसमें समय के साथ परिवर्तन भी देखा गया है। किसी क्षेत्र को नगर के रूप में वर्गीकृत करने का मानदंड एक निर्धारित न्यूनतम अनसंख्या; जनसंख्या घनत्व; गैर-कृषि क्षेत्रक में नियोजित जनसंख्या का अनुपात; पक्की सड़कों, विञ्चत्, जलापूर्ति और जलनिकासी जैसी अवसंरचनाओं तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपस्थिति जैसी किसी एक विशेषता अथवा विशेषताओं के संयोजन पर आधारित होता है।

इस खंड में, हम नगरीय क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं तथा परिघटनाओं पर चर्चा करेंगे। इसमें नगरीय क्षेत्रों की जनगणना संबंधी परिभाषा, नगरीय संकुलन (Urban Agglomeration), अति-नगरीकरण (Over-Urbanization), उप-नगरीकरण (Sub Urbanization), प्रति-नगरीकरण (Counter Urbanization) तथा जनगणना नगर (Census towns) शामिल हैं।





1961 की जनगणना में 'नगर (टाउन)' को विभिन्न आनुभविक परीक्षणों के आधार पर परिभाषित तथा निर्धारित किया गया था। इस हेतु अनिवार्य शर्तें निम्नलिखित थीं:

- 5000 की न्यूनतम जनसंख्या,
- जनसंख्या घनत्व कम से कम 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील,
- कार्यशील जनसंख्या का तीन-चौथाई भाग गैर-कृषि कार्यों में संलग्न हो,
- इस क्षेत्र में नगरों की कुछ विशेषताएं एवं सुविधाएँ अवश्य हों जैसे कि हाल ही में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, वृहद् आवासीय बस्तियां तथा पर्यटन महत्व और नागरिक सुविधाओं के स्थल।

A DO

2.1. नगरीय संकुल (Urban Agglomeration)

इस शब्द का प्रयोग पहली बार 1971 की जनगणना में किया गया था। प्राय: बड़ी रेलवे कॉलोनियाँ, विश्वविद्यालय परिसर, बन्दरगाह क्षेत्र, सैन्य परिसर इत्यादि किसी नगर या कस्बे की सांविधिक सीमा के दायरे में नहीं आते परन्तु इनसे संलग्न क्षेत्र होते हैं। ऐसे क्षेत्र स्वयं में नगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य नहीं होते, परन्तु यदि वे संलग्न नगर या कस्बे के साथ निरंतर विस्तारित होते हैं तो उन्हें नगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देना यथार्थवादी सिद्ध हो सकता है। ऐसी बस्तियां आउटग्रोथ (बहिर्बद्ध) के रूप में परिभाषित की जाती हैं तथा एक सम्पूर्ण गाँव अथवा गाँव के एक भाग को समाहित कर सकती हैं। ऐसे नगर अपनी आउटग्रोथ के साथ एक नगरीय इकाई के रूप में माने जाते हैं तथा 'नगरीय संकुल' कहलाते हैं।

2.2 अति-नगरीकरण (Over-Urbanization)

यह किसी नगर में या इसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीकरण की विशेषताओं के अत्यधिक विस्तार को संदर्भित करता है। यह नगरीय विशिष्टताओं के अत्यधिक विकास का परिणाम है। नगरीय गितविधियों और व्यवसायों के दायरे में विस्तार, उद्योगों जैसे द्वितीयक कार्यों के अत्यधिक अन्तर्वाह, एक जटिल नौकरशाही केन्द्रित प्रशासनिक नेटवर्क के वृद्धिशील एवं व्यापक विकास, जीवन की बढ़ती कृत्रिमता व यंत्रीकरण तथा निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय लक्षणों के प्रवेश के कारण, अतिनगरीकरण धीरे-धीरे किसी समुदाय के रीति-रिवाजों एवं परम्परावादी गुणों को प्रतिस्थापित कर देता है। मुंबई तथा कोलकाता ऐसे नगरों के प्रमुख उदाहरण हैं।

2.3 उप-नगरीकरण (Sub-Urbanization)

यह किसी नगर के अति-नगरीकरण से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जब किसी नगर की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि (ओवर क्राउडिंग) होती है तो इसके परिणामस्वरूप उप-नगरीकरण की घटना घटित होती है। दिल्ली इसका प्रतीकात्मक उदाहरण है। उप-नगरीकरण से तात्पर्य किसी नगर के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र का नगरीकरण है। यह निस्नलिखित विशेषताओं को प्रकट करता है-

- भूमि के 'नगरीय (गैर-कृषिगत) उपयोग' में तीव्र वृद्धि,
- नगर के आस-पास के क्षेत्रों का उसकी नगरपालिका की सीमा में समावेशन तथा
- नगर तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के मध्य सभी प्रकार के गहन संचार साधन।

2.4 प्रति-नगरीकरण (Counter-Urbanization)

यह एक जनांकिकीय तथा सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें लोग नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। पहली बार यह आंतरिक शहर में संसाधनों के अभाव तथा अत्यधिक भीड़-भाड़ (ओवर क्राउडिंग) की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप घटित हुआ था। प्रति नगरीकरण तब घटित होता है जब कुछ बड़े नगर ऐसी अवस्था में पहुँच जाते हैं, जिसमें उनकी वृद्धि रुक जाती है या वास्तव में उनके



आकार में ह्रास प्रारम्भ हो जाता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या उपनगरीय क्षेत्रों या छोटे शहरों की ओर प्रवास करने लगती है। इस प्रकार यह ग्राम-नगर उपांत (rural-urban fringe) में होने वाली अकस्मात वृद्धि है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारत में प्रति-नगरीकरण घटित हो रहा है।



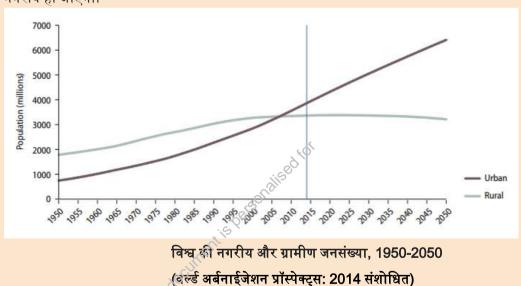
2.5 जनगणना नगर (Census Town)

2011 में जनगणना नगर की एक नवीन परिभाषा विकसित हुई है। 'जनगणना नगरों' वाला यह नगरीय वर्गीकरण भारत के छोटी कृषक बस्तियों तथा बड़े क़स्बाई बाजार के जैसी बस्तियों (जिनमें तीव्र और अकस्मात वृद्धि हो रही है) के मध्य अंतर स्थापित करने में सहायक है। एक जनगणना नगर के रूप में वर्गीकृत होने के लिए किसी गाँव को निम्नलिखित तीन मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है:

- उसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो,
- न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो, और
- पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75 प्रतिशत गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न हो।

नगरीकरण की वैश्विक प्रवृति (Global Trends In Urbanization)

वैश्विक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। इतिहास में पहली बार 2007 में, वैश्विक नगरीय जनसंख्या वैश्विक ग्रामीण जनसंख्या से अधिक हुई थी। तत्पश्चात विश्व की जनसंख्या मुख्य रूप से नगरीय बनी हुई है। विगत छह दशकों से विश्व, तीव्र नगरीकरण प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस प्रकार नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने की अपेक्षा की जा रही है। अत: यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व 2050 तक एक तिहाई ग्रामीण (34%) तथा दो-तिहाई (66%) नगरीय हो जाएगा।



3. नगरीकरण की प्रक्रिया (Process of Urbanization)

परिवर्तन की संरचनात्मक प्रक्रिया के रूप में नगरीकरण, सामान्यतः औद्योगीकरण से संबंधित है किन्तु यह सदैव औद्योगीकरण का परिणाम नहीं होता। नगरीकरण शहरों में वृहद् और लघु स्तर पर औद्योगिक, वाणिज्यिक, वित्तीय और प्रशासनिक संरचनाओं की स्थापना; परिवहन और संचार में तकनीकी विकास, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन गतिविधियों आदि के संकेंद्रण का परिणाम होता है। वस्तुतः औद्योगीकरण नगरीय क्षेत्रों में आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रदान करना संभव



बनाता है परन्तु कुछ परिस्थितियों में यह अति नगरीकरण की स्थिति उत्पन्न करता है। इस सम्बन्ध में भारत में एक विशिष्ट घटना देखी जा सकती है: भारत में औद्योगिक संवृद्धि तो हो रही है किन्तु जनसंख्या का कृषि से उद्योग की ओर उल्लेखनीय स्थानान्तरण नहीं हो रहा है, साथ ही नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है किन्तु कुल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो रही है। यद्यपि आनुपातिक रूप से, ग्रामीण से नगरीय गतिविधियों की ओर अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का बड़े स्तर पर प्रवसन निरंतर जारी है। यह नगरीय क्षेत्रों के विकास को अवरुद्ध करता है तथा साथ ही निरंतर बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी उत्पन्न करता है। भारतीय संदर्भ में, नगरीकरण को एक सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया और भौगोलिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है।



- एक सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में, यह विभिन्न नृजातीय, भाषाई और धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का सम्मिलन स्थल (मेल्टिंग-पॉट) है।
- आर्थिक प्रक्रिया के रूप में शहर, उत्पादक गतिविधियों के केंद्र बिंदु हैं। इनका अस्तित्व और विकास इनमें अन्तर्निहित आर्थिक गतिविधियों की क्षमता पर निर्भर करता है।
- भौगोलिक प्रक्रिया के अंतर्गत, यह व्यक्तियों के प्रवास अथवा आवासों के स्थानांतरण से संबंधित है
 और इसमें लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण सम्मिलित है।

इस प्रकार नगरीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण से संबंधित है, जिसने वृहत्तर भौगोलिक गतिशीलता, निम्न प्रजनन क्षमता, उच्च जीवन प्रत्याशा और वृद्ध लोगों की संख्या में वृद्धि जैसी प्रवृत्तियों को उत्पन्न किया है।

विस्तारशील नगर (Expanding Cities)

- अधिकांश मेगासिटी और बड़े शहर ग्लोबल साउथ (तृतीय विश्व के देशों, विकासशील एवं अल्पविकसित देशों तथा अल्पविकसित क्षेत्रों को सामूहिक रूप से ग्लोबल साउथ कहा जाता है) में स्थित हैं। भारत के सात शहरों को 2030 तक मेगासिटी के रूप में विकसित करना प्रस्तावित किया गया है। इनमें से चार शहर (अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद) वर्तमान के 5 -10 मिलियन जनसंख्या के साथ आगामी वर्षों में मेगासिटी का स्तर प्राप्त कर लेंगे।
- टोक्यो 38 मिलियन जनसंख्या संकुल वाला विश्व का सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद दिल्ली का स्थान है जिसकी जनसंख्या 25 मिलियन है।
- कई दशक पूर्व विश्व के सबसे बड़े नगरीय संकुल अधिकांशतः विकसित क्षेत्रों में विद्यमान थे, किन्तु आज के बड़े शहर ग्लोबल साउथ में संकेंद्रित हैं।
- हाल के वर्षों में कुछ शहरों की जनसंख्या में गिरावट देखी गयी है। इनमें से अधिकांशतः एशिया और यूरोप के निम्न प्रजनन क्षमता वाले देशों में स्थित हैं जहां की समग्र आबादी स्थिर है अथवा गिरावट के दौर में है। आर्थिक मंदी और प्राकृतिक आपदाओं ने कुछ शहरों में जनसंख्या की गिरावट में योगदान किया है।

r)(वर्ल्ड अर्बनाइज़ेशन प्रॉस्पेक्ट्स:

4. भारत में नगरीकरण (Urbanization in India)

भारत में नगरीकरण का लंबा इतिहास रहा है जो स्थानिक और सामयिक असम्बद्धताओं से युक्त है। यह सतत प्रक्रिया है जो अपने प्रारम्भ के बाद से अनवरत जारी है तथा शायद ही कभी मंद हुई हो। भारत में नगरीकरण को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। यह सिन्धु सभ्यता से प्रारम्भ होकर मुग़ल काल के दौरान उल्लेखनीय स्तर तक पहुँच गया। तत्पश्चात इस प्रक्रिया में ब्रिटिश शासन का भी



विशिष्ट योगदान रहा। स्वतंत्रता पश्चात् नगरीकरण के स्तर में तीव्र एवं अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में नगरीय परिदृश्य में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन हुए हैं:

 नए प्रशासनिक नगरों का निर्माण, बड़े नगरों के सिन्नकट नए औद्योगिक नगरों और टाउनिशप का निर्माण, एक लाख और दस लाख की जनसंख्या वाले नगरों में तीव्र वृद्धि, मिलन बस्तियों और ग्राम-नगर उपांत क्षेत्रों (संक्रमणशील क्षेत्र) में व्यापक वृद्धि, नगर नियोजन की शुरुआत और नागरिक सुविधाओं में सामान्य सुधार आदि।

भारत के तीव्र आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप वर्तमान में नगरीकरण की प्रक्रिया का त्वरित होना अपरिहार्य है। आर्थिक सुधार ने निवेश और संवृद्धि को प्रेरित किया है जो नागरिकों को आगे बढ़ने के समृद्ध अवसर प्रदान कर रहे हैं। शहरों में विकास और रोजगार की वृद्धि इस सन्दर्भ में एक शक्तिशाली चुम्बकीय कारक सिद्ध होगा। हालांकि, यदि इसे अनुकूल ढंग से प्रबंधित नहीं किया गया तो भारत की नगरीय जनसंख्या में होने वाली अपरिहार्य वृद्धि संपूर्ण व्यवस्था पर भारी दबाव डालेगी।

भारत को अधिक समावेशी होने के लिए, यह अनिवार्य है कि आर्थिक विकास और नगरीय जनसंख्या दोनों को अधिक समान रूप से वितरित किया जाए। अतः, भारत के लिए भविष्य के शहरों (cities of tomorrow) हेतु एक नियोजित दृष्टिकोण के बिना कोई भी अर्थपूर्ण दीर्घकालिक लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। वर्तमान नगरीय भारत संपूर्ण देश में विस्तारित बड़े और छोटे शहरों की एक विस्तृत शृंखला के साथ 'वितरित (distributed)' स्वरूप में परिलक्षित होता है। भारत में नगरीकरण के इसी डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल के प्रचलित रहने की संभावना है क्योंकि यह देश के संघीय ढांचे के अनुरूप है तथा यह सुनिश्चित करने में सहायक है कि प्रवसन प्रवाह (Migration Flow) किसी विशेष शहर या शहरों की ओर न हो। जैसे-जैसे नगरीय जनसंख्या और आय में वृद्धि होती जाती है वैसे- वैसे प्रत्येक आकार और प्रकार के शहरों में, सभी महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे जल, परिवहन, सीवेज ट्रीटमेंट तथा निम्न आय वर्ग हेतु आवास की मांग, पांच से सात गुना बढ़ जाती है। अतः यदि भारत की वर्तमान स्थिति निरंतर जारी रहती है तो आने वाले समय में शहरों को समृद्ध बनाए रखने के लिए आवश्यक नगरीय आधारभूत संरचना का गंभीर अभाव हो सकता है।

संभवतः राज्य सरकारों की अनिच्छा के कारण, निर्वाचित निकायों को 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अपूर्ण हस्तांतरण हुआ है। इसके अतिरिक्त, केवल कुछ ही शहरों द्वारा 2030 मास्टर प्लान को अपनाया गया है। इस मास्टर प्लान के तहत उच्चतम परिवहन भार, निम्न आय वर्ग हेतु सस्ते आवास की आवश्यकताओं और अलवायु परिवर्तन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सामान्यतः, ऐतिहासिक रूप से नगरपालिका और राज्य स्तर पर नगरीय सुधारों और परियोजनाओं को निष्पादित करने की क्षमता अपर्याप्त रही है।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का 31.1% भाग अर्थात 377 मिलियन लोग नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। यूनाइटेड नेशंस हैबिटैट वर्ल्ड सिटी 2016, रिपोर्ट का अनुमान है कि व्य**्यन ज**ने भहंस्स कृतिनशीरीय जनसंख्या

1981-2001 की अवधि में, भारत में नगरीकरण मुख्यतः शहरों की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि (लगभग 60%) से प्रेरित था। इसके पश्चात् ग्रामीण शहरी प्रवास, शहरों की सीमाओं का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों के रूप में पुनर्वर्गीकरण आदि कारकों का स्थान था।

परन्तु, 2001 से 2011 के मध्य, शहरों की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि का अंश कम होकर 44% हो गया, जबिक ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों के रूप में पुनर्वर्गीकरण के हिस्से में वृद्धि के साथ ग्रामीण शहरी

प्रवास का हिस्सा बढ़ कर 24% हो गया।

यह वृद्धि सराहनीय है, किन्तु भारत में नगरीकरण का विस्तार अन्य प्रमुख विकासशील देशों से काफी कम है। विश्व बैंक के अनुसार, 2015 में कुल जनसंख्या के अनुपात में शहरी जनसंख्या ब्राजील में 86%, चीन में 56%, इंडोनेशिया में 54%, मेक्सिको में 79% और दक्षिण कोरिया में 82% है।



5. नगरीकरण के सामाजिक प्र<u></u>भाव

(Social effects of Urbanization)

नगरीकरण वृहद सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं-

5.1 परिवार और नातेदारी (Family and Kinship)

नगरीकरण न केवल परिवार की संरचना को बल्कि अन्तः पारिवारिक एवं अंतर-पारिवारिक संबंधों तथा परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी प्रभावित करता है। नगरीकरण के कारण, सामुदायिक संबंधों में व्यवधान उत्पन्न होता है तथा प्रवासियों को पुराने संबंधों को नए संबंधों से प्रतिस्थापित करने एवं पुराने संबंधों को संतोषजनक तरीके से निभाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आई. पी. देसाई (1964) ने उल्लेख किया है कि यद्यपि नगरीय परिवारों की संरचना परिवर्तित हो रही है, तथापि परिवारों में व्यक्तिवाद (individualism) की भावना में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि 74 प्रतिशत परिवार आवासीय रूप से एकल (Nuclear) परन्तु दायित्वों और संपत्ति के सन्दर्भ में संयुक्त थे, 21 प्रतिशत परिवार संपत्ति सहित आवासीय एवं कार्यात्मक रूप में संयुक्त थे तथा केवल 5 प्रतिशत परिवार एकल थे।

एलिन रॉस (1962) ने बैंगलोर में मध्यम और उच्च वर्गों के 157 हिंदू परिवारों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि-

- लगभग 60 प्रतिशत परिवार एकल हैं।
- वर्तमान प्रवृत्ति, पारंपरिक संयुक्त परिवारों की संरचना को खंडित कर एकल पारिवारिक संरचना की ओर और अंततः एकल पारिवारिक इकाई की ओर आगे बढने की है।
- वर्तमान में नगरीय भारत में छोटे संयुक्त परिवार, पारिवारिक जीवन का सर्वाधिक विशिष्ट रूप हैं।
- दूरी के कारण पारस्परिक सम्बन्ध कमजोर हो रहे हैं या टूट रहे हैं।

5.2 नगरीकरण और जाति

(Urbanization and caste)

- सामान्य रूप से यह माना जाता है कि जातियां ग्रामीण भारत की जबिक वर्ग नगरीय भारत की विशेषता है तथा नगरीकरण के कारण जाति का वर्ग में रूपांतरण हो रहा है। परन्तु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जाति व्यवस्था शहरों और गांवों में लगभग एकसमान रूप से व्याप्त है। हालांकि इनमें महत्वपूर्ण संगठनात्मक भिन्नताएँ विद्यमान हैं।
- वस्तुतः जातिगत पहचान नगरीकरण, शिक्षा तथा व्यक्तिगत उपलब्धि एवं आधुनिक स्टेटस सिम्बल की ओर अभिविन्यास के विकास के साथ कम हो जाती है। यह चिह्नित किया गया है कि पश्चिमीकृत अभिजात वर्ग के मध्य जाति आधारित संबंधों से वर्ग आधारित संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।



हालांकि जाति व्यवस्था निरंतर विद्यमान है और शहरी सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है, जबिक कुछ अन्य क्षेत्रों में इसने अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जातिगत संबद्धता या जातिगत एकता उतनी सुदृढ़ नहीं है। शहरों में जाति पंचायत बेहद कमजोर हैं। यहाँ कार्यस्थल और घरेलू परिस्थिति के मध्य एक द्वैत की स्थिति विद्यमान है तथा जाति और वर्ग स्थिति, दोनों ही सह-अस्तित्व में बने हुए हैं।



5.3 नगरीकरण और महिलाओं की स्थिति

(urbanization and status of women)

- महिलाएं ग्रामीण-शहरी प्रवासियों के एक महत्वपूर्ण वर्ग का निर्माण करती हैं। वे विवाह के समय भी प्रवास करती हैं और उस समय भी जब वे अपने गंतव्य स्थल में सम्भाव्य कर्मचारी होती हैं। जहाँ मध्यमवर्गीय महिलाएं व्हाइट कॉलर नौकरियों और व्यवसायों में नियोजित होती हैं वहीं निचले वर्ग की महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही महिलाएं औपचारिक क्षेत्र में भी औद्योगिक कर्मचारियों के रूप में कार्यरत होती हैं।
- महिलाओं की एक बड़ी संख्या व्हाइट कॉलर नौकरियां प्राप्त कर विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश कर रही है। इन व्यवसायों ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके परिणामस्वरूप स्वायत्तता में वृद्धि के साथ-साथ कार्य के श्रमसाध्य व बढ़े हुए घंटों एवं व्यावसायिक निष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिली है। हालाँकि परंपरागत और सांस्कृतिक संस्थानों की स्थिति पूर्ववत बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मूल्यों का संकट और मानकों के सन्दर्भ में दुविधा की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से प्रबुद्ध महिलाएँ सामाजिक और पेशेवर जीवन की दोहरी भूमिकाएं निभाने के लिए बाध्य हैं।
- तुलनात्मक रूप से शिक्षित और उदार होने के कारण नगरीय महिलाओं की स्थिति ग्रामीण महिलाओं की तुलना में उच्च है। हालांकि श्रम बाजार में, अभी भी महिलाओं के लिए एक प्रतिकूल स्थिति विद्यमान है।

6. नगरीकरण की समस्याएँ

(Problems of Urbanization)

भारत में नगरीकरण के प्रतिरूप को क्षेत्रीय एवं अंतरराज्यीय विविधता, वृहत पैमाने पर ग्रामीण-शहरी प्रवासन, अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं, मिलन बस्तियों में वृद्धि तथा अन्य संबद्ध समस्याओं द्वारा चिह्नित किया जाता है। भारत के विभिन्न भारों में नगरीकरण में व्याप्त प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं:

6.1 आवास एवं भूमि के बढ़े हुए मूल्य

(Housing and Inflated Land Prices)

भारत में भूमि के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि का मुख्य कारण रियल एस्टेट में अवैध धन का प्रवाह है। इसलिए, काले धन पर नियंत्रण का एक लाभकारी पार्श्व प्रभाव यह होगा कि कम आय वाले परिवारों हेतु आवास अधिक वहनीय मूल्य पर उपलब्ध होंगे। भूमि में काले धन के प्रवाह को प्रोत्साहित करने का एक महत्त्वपूर्ण कारक उच्च स्टाम्प शुल्क है। इस शुल्क को कम करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर कार्य करना भूमि के मुल्यों में कमी करने में सहायक सिद्ध होगा।

इसके अतिरिक्त भारत में कृत्रिम रूप से उच्च शहरी संपत्ति मूल्यों में कम से कम चार आपूर्ति पक्षीय कारकों ने भी योगदान दिया है। ये कारक निम्नलिखित हैं:

